www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 उमर खालिद के समर्थन में उतर कर...

3 गरिमापूर्ण, अनुशासित एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से...

4 तारा सुतारिया के खिलाफ चलाया गया नेगेटिव...

वर्ष: 10 | अंक: 71 | दिल्ली, शनिवार, 3 जनवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

आरएसएस अर्धसैनिक संगठन नहीं, भाजपा को देखकर निष्कर्ष निकालना बड़ी भूल: मोहन भागवत

नई दिल्ली (एजेन्सी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि वर्दी और शारीरिक अभ्यास के बावजूद संघ कोई अर्धसैनिक संगठन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को देखकर आरएसएस के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करना एक बड़ी भूल होगी। भागवत ने यहां प्रबुद्धजनों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को एकजुट करने और उसमें आवश्यक गुण व सद्गुण विकसित करने का कार्य करता है, ताकि भारत दोबारा किसी विदेशी शक्ति के अधीन न जाए। उन्होंने कहा, हम वर्दी पहनते हैं, पथ संचलन करते हैं और दंड अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर कोई इसे अर्धसैनिक संगठन समझता है तो यह भूल होगी। उन्होंने कहा कि संघ एक अनूठा संगठन है, जिसे समझना आसान नहीं है।

भीषण सर्दी में भी अडिग है देश की सुरक्षा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। देश के एक बड़े हिस्से में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे मौसम में जब आम लोग घरों में कंबलों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं, तब भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों में डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और बर्फ से ढकी पहाड़ियों तक, सुरक्षा बलों का जज्बा इस भीषण ठंड में भी कमजोर नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो सुबह तड़के कड़कड़ाती ठंड के बीच 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। India Gate के आसपास घना कोहरा और सर्द हवाओं के बीच CRPF के जवान पूरे अनुशासन के साथ परेड अभ्यास करते नजर आ रहे हैं।

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन

संजना भारती/पीआईबी

चेन्नई। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने चेन्नई स्थित डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान के 34वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

उपराष्ट्रपति ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उतीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन में एक नए चरण का आरंभ है जिसमें अधिक दायित्व और अवसर हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तीर्ण विद्यार्थी अपने व्यावसायिक ज्ञान, करुणा और प्रतिबद्धता से समाज में सकारात्मक योगदान देंगे।

तमिलनाडु की ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा और समुद्री व्यापार केंद्र होने की चर्चा करते हुए, श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यहीं के तटों से व्यापारियों ने भारत के विचारों, नैतिकता और संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया, जो राष्ट्र की विश्वास से भरी सभ्यतागत भागीदारी और सीखने तथा आदान-प्रदान के प्रति खुलेपन के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 की भविष्य दृष्टि योजना का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नागरिक, खासकर युवाओं की सक्रिय

भागीदारी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण के इस लक्ष्य में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया।

तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव की चर्चा करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियां सभी क्षेत्रों में बदलाव ला रही हैं और इसमें निरंतर सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित तौर पर कौशल विकास करने, आजीवन सीखने की मानसिकता अपनाने और अपने मूल विषयों से परे भी नई तकनीकों से जुड़ने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता-नैतिकता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित होनी चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने संस्थान परिसर से बाहर के जीवन के बारे में विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि सफलता और विफलता जीवन के अभिन्न अंग हैं और दोनों का सामना संतुलन, दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता के साथ करना चाहिए। उन्होंने उत्तीर्ण विद्यार्थियों से कम समय में सफल होने के शॉर्टकट और अस्वस्थ तुलनाओं से बचने की सलाह दी और उनसे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, निरंतर प्रगति और अपनी विशिष्ट क्षमताओं की पहचान कर आगे बढने के लिए प्रेरित किया।

उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन के समापन में, उत्तीर्ण स्नातकों से उद्देश्यपूर्ण और सेवापूर्ण जीवन जीने तथा व्यक्तिगत उत्कृष्टता हासिल कर सामूहिक रूप से राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एम.ए. सुब्रमणियन; डॉ. एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान के कुलाधिपति डॉ. ए.सी. षणमुगम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP-III की पाबंदियां हटीं

जमीनी कार्रवाई पहले जैसी ही जारी रहेगी: सिरसा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। CAQM की सब-कमेटी द्वारा GRAP के स्टेज-III की पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हवा में आया सुधार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार हो रही जमीनी कार्रवाई का नतीजा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कल 380 था, घटकर 236 दर्ज किया गया। वहीं बवाना में अदक 141 रहा, जो अच्छी हवा का संकेत है।

श्री सिरसा ने कहा, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, धूल और खुले में कचरा फेंकने जैसे हर बड़े स्रोत पर सख़्त कार्रवाई की गई है। इसके साथ-साथ तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर हमारी कोशिशों को और मजबूत किया गया है।

मंत्री ने साफ किया कि भले ही GRAP-III की पाबंदियां हटाई गई हों, लेकिन जमीनी स्तर पर काम की रफ़्तार और सख़्ती में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा, यह ढील देने का समय नहीं है। अब तक जो हासिल हुआ है, उसे और मजबूत करने का समय है। हर छोटी

सफलता हमें रोज दिल्ली की हवा बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है।

पिछले 24 घंटों में पर्यावरण विभाग और संबंधित एजेंसियों ने प्रदूषण रोकने के लिए बड़े स्तर पर काम किया: वाहन प्रदूषण से जुड़े 6,596 चालान। शहर के अलग-अलग इलाकों से 12,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। धूल कम करने के लिए 6,261 किमी सड़कों की मशीन से सफाई। 2,315 मीट्रिक टन C&D वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण। अवैध कचरा फेंकने के खिलाफ 405 निरीक्षण, 156 पर कार्रवाई। 40 प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम के बिंदुओं को सुधारा गया। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 99 हल्के वाहनों पर चालान।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर काम कई गुना तेज हुआ है। औद्योगिक इलाकों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने से लेकर ट्रैफिक वाले इलाकों और हॉटस्पॉट्स पर स्मॉग गन और एंटी-स्मॉग वाहनों की तैनाती तक, हर मोर्चे पर सीधी कार्रवाई की जा रही है।

श्री सिरसा ने कहा, पिछले एक साल में दिल्ली ने प्रदूषण नियंत्रण के नए रास्तों पर तेजी से काम किया है, चाहे वह पुराने कचरे की बायो-माइनिंग को रफ़्तार देना हो या उद्योग और परिवहन क्षेत्र में साफ तकनीक को बढ़ावा देना। इन संयुक्त कोशिशों का असर अब साफ दिख रहा है।

सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा, दिल्ली की यह लड़ाई लगातार चलने वाली है। हर दिन हम सीख रहे हैं, अपने तरीकों को बेहतर बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज की प्रगति हमें कल और बेहतर करने की हिम्मत देती है।

फसल खरीद में लापरवाही पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख, दोषी अधिकारी-कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई-मुख्यमंत्री सैनी

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल खरीद व्यवस्था में आई अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक किसान की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वहीं गलत खरीद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां फसल खरीद प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने संबंधित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आगामी खरीद सीजन के दौरान फील्ड में नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसान की सही उपज बिना किसी बाधा के एमएसपी पर खरीदी जा सके। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में पूर्व में उजागर हुई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी खरीद सीजन में इस प्रकार की कोई भी समस्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल खरीद में संलिप्त पाए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। इससे फील्ड स्तर पर यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि गलत कार्य करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी शेलर या आढ़ती द्वारा मिलीभगत कर भारी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ भारी पेनल्टी भी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शेलरों की जांच के लिए संबंधित विभाग की समिति ही जाए, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जांच पर न जाए। यदि ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसान के खेत से मंडी तक और मंडी से शेलर तक पूरी फसल की पूर्ण रूप से तकनीकी निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, इसलिए सभी फसलों का सटीक डाटा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट होना अनिवार्य है। इसके लिए ग्राम सचिवों, पटवारियों के साथ-साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी जोड़ा जाए ताकि कितने एकड़ में कितनी फसल खड़ी है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही हरसैक से प्राप्त रिपोर्ट के साथ भी आपसी तालमेल सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में प्रदेश की कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों को भी शामिल कर उनकी विशेषज्ञ भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में बताया गया कि आगामी खरीफ फसल खरीद सीजन के लिए विभाग द्वारा उन्नत तकनीक आधारित विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को मंडी में फसल बेचने पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही नई तकनीकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को डिविजनल स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

बैठक में वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल सहित संबंधित खरीद एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समाधान शिविरों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए-सैनी

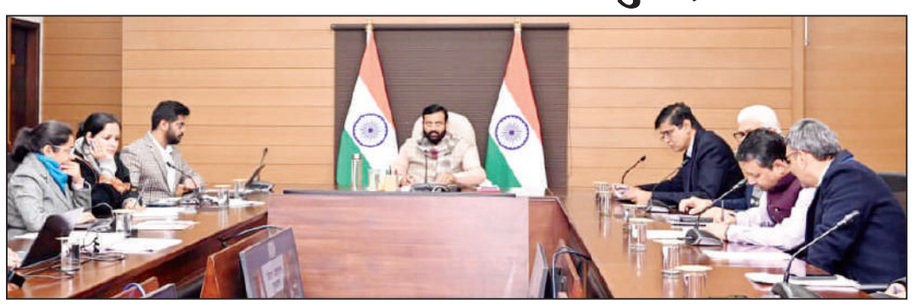

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविरों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुँचाई जाए, जिसमें लोगों को शिविरों के आयोजन का दिन और समय की पूरी जानकारी मिल सके, ताकि वे अपनी समस्याएँ दर्ज करवा सकें और उनका समाधान करवा सकें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश चंडीगढ़ में समाधान शिविर की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में सभी जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को जिला उपायुक्त अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ आगे भेजें। साथ ही जब तक किसी शिकायत का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक उसे जिला स्तर पर पेंडिंग रखा जाए। बैठक में बताया गया कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक पिछले छह महीनों में कुल 17,699 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। समाधान शिविरों में तय समय सीमा में हल की गई शिकायतों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी समाधान शिविरों में आने वाली सभी शिकायतों का तय समय सीमा में निपटान सुनिश्चित करें।

प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार और वीरवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नागरिक अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। यदि समाधान शिविरों में किसी भी स्तर पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही पाई गई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला अम्बाला के एक गांव में पानी की निकासी से संबंधित समाधान शिविर में प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त अम्बाला को इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस समिति में संबंधित विभाग के एक्सईएन, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) तथा मार्केट कमेटी का एक कर्मचारी शामिल किया जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी विवेक कालिया, बी.बी. भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश बन रहा है देश का उभरता दूरसंचार पावरहाउस

योगी सरकार का विकास मॉडल, त्वरित गति से हो रहा है औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दूरसंचार क्षेत्र की तेजी से प्रगति हो रही है। प्रदेश में मोबाइल, ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं का विस्तार शहरी के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में मजबूती से हो रहा है। इस विस्तार का सबसे बड़ा कारण सरकारी नीतिगत समर्थन और निजी निवेश है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र का त्वरित गति से दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि देश के अग्रणी दूरसंचार बाजारों में उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से शामिल है। योगी सरकार के विकास मॉडल से प्रदेश के डिजिटल क्षेत्र को नया आयाम मिल रहा है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में देश भर में कुल वायरलेस मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 1173.88 मिलियन रही। अक्टूबर 2025 में यह संख्या 1171.87 मिलियन था। इसमें उत्तर प्रदेश पूर्व और उत्तर प्रदेश पश्चिम दोनों लाइसेंस्ड सेवा क्षेत्रों की भागीदारी विशेष रही है। उपभोक्ता गतिविधि के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बना हुआ है। नवंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश पूर्व में 1.97 मिलियन और

उत्तर प्रदेश पश्चिम में 1.35 मिलियन पोर्टिंग अनुरोध दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रदेश में मोबाइल सेवाओं की मांग अधिक है।

फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस विशेष कर 5-जी आधारित सेवाओं में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। नवंबर 2025 के अंत तक देश में कुल 5-जी एफडब्ल्यूए उपभोक्ताओं की संख्या 10.41 मिलियन दर्ज की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश पूर्व में 0.79 मिलियन और उत्तर प्रदेश पश्चिम में 0.62 मिलियन उपभोक्ता शामिल हैं। केवल एक महीने के भीतर इन दोनों क्षेत्रों में हजारों नए उपभोक्ताओं का जुड़ना यह संकेत देता है कि सरकार की डिजिटल कनेक्टिविटी नीति का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। दूर-दराज के गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर खोल रही है।

वायरलाइन सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने स्थिर वृद्धि दर्ज की है। नवंबर 2025 के अंत तक देश में कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 47.05 मिलियन रही। उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और शहरी आवासीय क्षेत्रों में वायरलाइन कनेक्शन की मांग बनी हुई है।

योगी सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस सेवाओं को व्यापक रूप से लागू किए जाने से विश्वसनीय और सुरक्षित कनेक्टिविटी की आवश्यकता बढ़ी है जिससे वायरलाइन नेटवर्क को मजबूती मिली है। सक्रिय मोबाइल उपभोक्ताओं के मामले में भी प्रदेश की स्थिति सशक्त बनी हुई है। अक्टूबर की तुलना में नवंबर 2025 तक में देश भर में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं में से 1090.91 मिलियन उपभोक्ता सक्रिय पाए गए। ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ई-शिक्षा और टेली मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल टावरों की संख्या में वृद्धि और 5-जी तकनीक को बढ़ावा देने से उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

भारत के इरादों को गलत समझने से बचाने के लिए संवाद जरूरी: एस. जयशंकर

नई दिल्ली (एजेन्सी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत के इरादों को गलत तरीके से समझने की स्थिति से बचने के लिए अन्य देशों के साथ प्रभावी संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए जयशंकर ने कहा, लोगों को आपको गलत समझने से रोकने का तरीका संवाद है। यदि आप अच्छी तरह, स्पष्ट और ईमानदारी से संवाद करते हैं तो अन्य देश और लोग उसका सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, विश्वभर में बहुत से लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व करते हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम ऐसा क्यों न करें। जयशंकर ने कहा, बहुत कम प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आज प्रमुख आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के रूप में अस्तित्व में हैं और भारत उनमें से एक है। हमारे पास अपने अतीत की ऐसी समझ है जो बहुत कम देशों के पास है... यह लोकतांत्रिक राजनीतिक मॉडल को अपनाने का हमारा निर्णय ही था, जिसने लोकतंत्र के विचार को एक सार्वभौमिक राजनीतिक अवधारणा बना दिया। उन्होंने कहा, यदि हमने यह रास्ता नहीं चुना होता तो लोकतांत्रिक आदर्श क्षेत्रीय और संकीर्ण ही रह जाता।... पश्चिम के साथ साझेदारी भी महत्वपूर्ण है और इसी तरह हम दुनिया को आकार देते हैं। जयशंकर ने कहा कि देशों ने घरेलू स्तर पर विकास करने और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के माध्यम से प्रगति की है तथा अंतरराष्ट्रीय परिवेश का इस तरह उपयोग किया है जिससे उन्हें लाभ भी मिला और उनका योगदान भी रहा।

पंजाब मोहाली से अंतरराष्ट्रीय कार्यों का विस्तार करेगा: मुख्यमंत्री मान

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहां शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से और अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की वकालत करते हुए कहा कि विदेशी कार्यों के विस्तार से पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणियां चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) द्वारा पंजाब सरकार को 19 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश सौंपते समय की, जिसे उन्होंने हवाई अड्डे के सतत विकास और केंद्र-पंजाब की मजबूत साझेदारी का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि मोहाली से मजबूत वैश्विक हवाई संपर्क उद्यमियों और व्यापारियों के लिए पहुंच को आसान बनाएगा साथ ही राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन करेगा और पंजाब को अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करेगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) के अधिकारियों,

जिन्होंने मुख्यमंत्री को 19 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश चेक भेंट किया, से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरंतर विकास केंद्र और पंजाब सरकारों के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मोहाली से अंतरराष्ट्रीय कार्यों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि राज्य को विश्व के विभिन्न स्थानों से जोड़ा जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन में मदद मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र और विश्व के उद्यमियों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की राज्य में सुगम आवाजाही में भी मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे से अधिक उड़ानें शुरू करने से क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी तथा साथ ही यह कदम दुनिया भर के प्रमुख उद्यमियों को राज्य में बड़ा निवेश करने के लिए आकर्षित करेगा।

सम्पादकीय

पत्रकार से अभद्रता!

पुराने साल के बीतने और नए साल के आने के दरम्यान मध्यप्रदेश से एक अच्छी और एक बुरी खबर आई। बुरी खबर यह कि देश के स्वच्छतम शहरों में शुमार राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की वजह से फैले संक्रमण ने गंभीर रूप ले लिया है। पिछले लगभग एक हफ्ते से दूषित पानी से बीमार होने की खबर आ रही थी। फिर पता चला कि मुख्य जल आपूर्ति लाइन में लीकेज के कारण सीवरेज का पानी मिलने से सैकड़ों लोग उल्टी-दस्त के शिकार हो गए हैं। कम से कम 13 लोगों की तो जान ही जा चुकी है और कई अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में लगातार भाजपा का शासन बना हुआ है। 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीता भी था, लेकिन कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से भाजपा ने गिरवा दिया और फिर से अपनी सरकार बना ली। इंदौर के सभी 9 विधायक भाजपा से हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, महापौर भी भाजपा के हैं और सबसे बढ़कर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी भाजपा से ही हैं। इसके बावजूद अगर इतने लोग दूषित जल से मर जाएं, तो फिर नैतिकता यही कहती है कि जिम्मेदार लोगों को फौरन इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए। लेकिन मोदीजी के नए भारत में इस्तीफे नहीं होते, ये बात तो खुद राजनाथ सिंह कह चुके हैं। इस नए भारत में जनप्रतिनिधि मीडिया को सवाल पूछने का हक भी नहीं देते हैं, यह बात भी अब मोदी सरकार को और भाजपा को आधिकारिक तौर पर कह देनी चाहिए। क्योंकि लगातार ऐसे प्रकरण हो रहे हैं जिसमें सवाल पूछने वाले पत्रकार से बदसलूकी हो रही है। तो इस बुरी खबर के बीच अच्छी खबर ये है कि भाजपा भले ही सवाल पूछने का हक न दे, लेकिन देश में अभी कुछ पत्रकार बचे हैं जो न केवल सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि मंत्री की तरफ से गलत भाषा के इस्तेमाल पर खुल कर विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय से एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने दूषित जल प्रकरण पर सवाल किए तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि फोकट के प्रश्न मत पूछो, श्री द्वारी इस पर भी नहीं रुके और उन्होंने प्रतिवाद किया, साथ ही कहा कि मैं वहां होकर आया हूं, तो उन्होंने कहा कि क्या घंटा होकर आए हो। इस निम्नस्तरीय भाषा पर अनुराग द्वारी ने कैलाश विजयवर्गीय को सीधे-सीधे भाषा की तमीज का पाठ पढ़ा दिया और कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, हालांकि इसके बाद भी श्री विजयवर्गीय के साथ के लोगों ने अनुराग द्वारी को ही रोकने की कोशिश की कि हमारे नेता हैं, उनसे ऐसी बात नहीं की जा सकती। दरअसल मोदी-शाह के युग की भाजपा के कई नेताओं को यह खुशफहमी है कि उनसे सवाल नहीं किया जा सकता, या उनकी सरकार की खामियों पर टोका नहीं जा सकता। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक पत्रकार को डपटते हुए कहा था कि मैं आपके मालिक से बात करूंगी। ये सीधे-सीधे पत्रकार को धमकी ही थी और इसमें जितनी गलती नेता की है, उतनी ही गलती उन मीडिया मालिकान की भी है, जो सत्ता से नजदीकी बढ़ाकर अपने लिए वित्तीय, सियासी या अन्य किस्मों के लाभ लेते हैं और बदले में आदर्शों को गिरवी रख देते हैं। मीडिया घरानों ने जिस तरह सत्ता के चरणों में खुद को झुका दिया है, उसी का नतीजा है कि अब पत्रकारों के सवालों का जवाब देना तो दूर उनसे शिष्टाचार से बातें भी नहीं की जातीं। अभी दो दिन पहले प.बंगाल में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पत्रकार से कहा कि तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। जबकि उन पत्रकार ने केवल यही पूछा था कि 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में भेजने का नियम अभी के नेताओं पर भी लागू होगा। पत्रकार ने इशारों में नरेन्द्र मोदी के रिटायरमेंट की बात छेड़ी थी, जिस पर अमित शाह बिफर पड़े। वे चाहते तो सीधे-सीधे इसका जवाब दे सकते थे। लेकिन सत्ता की हनक ही इतनी है कि वे हर किसी को अपने से निम्नतर समझने लगे हैं। पत्रकार उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है कि उससे तुम कहकर बात की जाए, लेकिन अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ने यही किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि लगातार हो रहा है, जिससे देश में मीडिया की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा दोनों पर आंच आई है। लेकिन इस दौर में जब अनुराग द्वारी जैसे लोग संयमित तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए पत्रकारिता के मापदंडों को ऊंचा उठाए रखते हैं, तो फिर उम्मीद जागती है कि मीडिया को पूरी तरह गुलाम होने से बचाया जा सकता है। रहा सवाल मध्यप्रदेश के इंदौर वाटरगेट का, तो इसमें फिलहाल सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है।

जयंती

सावित्रीबाई फुले

जन्म-3 जनवरी, 1831; मृत्यु-10 मार्च, 1897, भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्या और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थीं। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया। जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछात मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें 'मराठी की आदिकवयित्री' के रूप में भी जाना जाता था।

पुण्यतिथि

मोहन राकेश

जन्म: 8 जनवरी, 1925; मृत्यु: 3 जनवरी, 1972, 'नई कहानी आन्दोलन' के साहित्यकार थे। हिन्दी नाटक के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ, जब स्वाधीनता के बाद पचास के दशक में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज्वार देश में जीवन के हर क्षेत्र को स्पन्दित कर रहा था। उनके नाटकों ने न सिर्फ.नाटक का आस्वाद, तेवर और स्तर ही बदल दिया, बल्कि हिन्दी रंगमंच की दिशा को भी प्रभावित किया। आधुनिक हिन्दी साहित्य काल में मोहन राकेश ने अपने लेखन से दूर होते हिन्दी साहित्य को रंगमंच के करीब ला दिया और स्वयं को भारतेन्दु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के समकक्ष खड़ा कर दिया।

कल मिलेंगे

पति और पत्नी में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी
इतने में पति स्टूल पर चढ़कर फंदा पंखे में डालने की
कोशिश करने लगा
पत्नी-हो गया क्या, जो करना चाह रहो हो
पति-क्यों क्या हुआ?
पत्नी-जरा जल्दी करो मुझे स्टूल की जरूरत है....

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

उमर खालिद के समर्थन में उतर कर जोहरान मामदानी ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है

उमर खालिद कोई साधारण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को वैश्विक मंच से नैतिक समर्थन देना न केवल भारत के लिए गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। इससे यह संदेश जाता है कि दंगों और हिंसा से जुड़े आरोपों को वैचारिक खोल पहनाकर महिमामंडित किया जा सकता है

-नीरज कुमार दुबे

न्यूयार्क के मेयर जोहरान मामदानी की ओर से भारत में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भेजे गए एक पत्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह पत्र उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के दौरान दिया गया और इसमें मामदानी ने खालिद के विचारों की तारीफ करते हुए लिखा कि वे उनके बारे में सोच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है।

इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आलोचकों का कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दंगों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। हम आपको याद दिला दें कि उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोप हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में किसी विदेशी जनप्रतिनिधि की ओर से सहानुभूति और प्रशंसा का सार्वजनिक संकेत कई सवाल खड़े करता है। हम आपको बता दें कि मामदानी के पत्र को सिर्फ एक व्यक्तिगत संदेश नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में भी इस कदम को असहज माना गया है। भारत में यह तर्क उभरा है कि यदि हर देश का स्थानीय नेता दूसरे देश के न्यायिक मामलों पर टिप्पणी करने लगे तो संप्रभुता और संस्थागत सम्मान पर आंच आएगी।

देखा जाये तो जोहरान मामदानी का यह कदम साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। सवाल सीधा है। सवाल उठता है कि न्यूयार्क के मेयर को यह अधिकार किसने दिया कि वह भारत के दंगों से जुड़े एक आरोपी की तारीफ करे और उसे नैतिक समर्थन दे। मामदानी को समझना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सक्षम है, संवैधानिक है और अपने फैसले खुद लेने में समर्थ है।

उमर खालिद कोई साधारण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को वैश्विक मंच से नैतिक समर्थन देना न केवल भारत के लिए गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। इससे यह संदेश जाता है कि दंगों और हिंसा से जुड़े आरोपों को वैचारिक खोल पहनाकर महिमामंडित किया जा सकता है। यह संदेश उन तत्वों के लिए संजीवनी का काम करता है जो अराजकता और टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। मामदानी को यह समझना चाहिए था कि भारत का आंतरिक कानून और व्यवस्था किसी विदेशी राजनेता की राय का मोहताज नहीं। यदि उन्हें मानवाधिकार की इतनी ही चिंता है, तो उन्हें अपने देश में चल रही हिंसा, नस्लीय तनाव और अपराध की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत में न्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पत्रों के जरिये।

इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी गलत असर डाल सकता है। जब वहां के नेता दंगों के आरोपी की तारीफ करते हैं, तो यह वहां मौजूद कट्टर और हिंसक विचारधारा के लोगों का हौसला बढ़ाता है। वे इसे यह कहकर पेश कर सकते हैं कि उनके विचारों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। यह लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। लोकतंत्र का अर्थ कानून का शासन है, न कि आरोपियों का महिमामंडन।

यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र की बुनियाद एक दूसरे की संस्थाओं के सम्मान पर टिकी होती है। जब कोई विदेशी नेता भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है या एक पक्ष को नैतिक ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश करता है, तो यह आपसी विश्वास को चोट पहुंचाता है। यह न तो कूटनीतिक मर्यादा के अनुरूप है और न ही जिम्मेदार राजनीति का उदाहरण।

मामदानी का पत्र उन तमाम भारतीय नागरिकों की भावनाओं का भी अपमान है जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपने परिजन खोए, जिनकी दुकाने जलीं और जिनका जीवन तबाह हुआ। उनके लिए दंगे कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे में दंगों के मास्टरमाइंड की तारीफ करना घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

भारत को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि वह लोकतांत्रिक है या न्यायप्रिय। यहां की अदालतें स्वतंत्र हैं और फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं। यदि उमर खालिद निर्दोष है, तो वह अदालत से बरी होगा। यदि दोषी है, तो सजा पाएगा। इसमें किसी विदेशी मेयर के भावनात्मक पत्र की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जोहरान मामदानी का यह कदम गैर जिम्मेदार, दखल देने वाला और भड़काऊ है। भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान तभी संभव है, जब हर देश अपनी सीमाएं पहचाने और दूसरों की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से बचे। यही संतुलन वैश्विक शांति और आपसी सम्मान की असली कसौटी है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बढ़ते शहरीकरण में पिछड़ता कचरा प्रबंधन

आज भारत के जितने बड़े शहर हैं वहां उतने ही बडे कचरे के ढ़ेर मिलेंगे। दिल्ली का गाजीपुर, मुंबई का देवनार लैंडफिल कचरे के पहाड़ बन चुके हैं जिनसे निकलने वाली मीथेन गैस आसपास के निवासियों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है। इससे न केवल मानवीय स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि वहां की मिट्टी और हवा भी बुरी तरह से प्रदूषित होती है

-अशोक चौधरी

आजादी के बाद भारत के हर क्षेत्र में विकास के साथ-साथ बहुत सी समस्याएं भी खड़ी हुई हैं जिनका स्थाई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इनमें शहरों के ठोस कचरे का प्रबंधन एक गंभीर समस्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी 30 प्रतिशत थी और इसके 2030 तक 40 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। शहरी आबादी लगभग 2.3 प्रतिशत सलाना की दर से बढ़ रही है और इससे आर्थिक सामाजिक परिदृश्य में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बढती जनसंख्या के कारण पर्याप्त आवास, परिवहन और अन्य सेवाओं की कमी के साथ-साथ कचरा प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है।

आज भारत के जितने बड़े शहर हैं वहां उतने ही बडे कचरे के ढ़ेर मिलेंगे। दिल्ली का गाजीपुर, मुंबई का देवनार लैंडफिल कचरे के पहाड़ बन चुके हैं जिनसे निकलने वाली मीथेन गैस आसपास के निवासियों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है। इससे न केवल मानवीय स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि वहां की मिट्टी और हवा भी बुरी तरह से प्रदूषित होती है। गाजीपुर लैंडफिल से प्रतिवर्ष 3000 टन से अधिक मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।

वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि गाजीपुर और देवनार लैंडफिल के पड़ौस में बसे लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है और श्वसन की अन्य बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हम इस समय 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है। वर्तमान में यह लगभग 14.50 करोड़ टन प्रतिवर्ष की दर से पैदा हो रहा है और 2047 तक इसके 26 से 30 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत गोबर को खाद और बायोगैस में बदलने तथा प्रबंधित करने की केंद्रीय योजना 'गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन' (गोबर-धन योजना) जैसी कोशिशों से रचनात्मक काम किया जा रहा है, लेकिन जिस मात्रा में ठोस कचरा पैदा हो रहा है, उसका निपटान नहीं हो पा रहा है।

भारत में 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986' और 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016' के तहत एक नियमावली बनाई गई है, लेकिन उसका प्रभावशाली क्रियान्वयन होना आवश्यक है, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु जागरूकता पैदा हो सके। हालांकि नगरपालिकाओं द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण एवं डंपिंग स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि उसका कंपोस्ट बनाने में उपयोग किया जा सके, लेकिन घरेलू और संस्थागत स्तर पर कचरे का पृथक्करण नहीं किया जा रहा है। सभी प्रकार के कचरे को एक ही डस्टबिन में डाल दिया जाता है जो आगे जाकर बड़ी समस्या पैदा करता है।

ठोस कचरे में बड़ा भाग ऐसा होता है जिससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। यदि घरेलू स्तर पर ही उस कचरे का पृथक्करण प्रारंभ कर दिया जाए तो नगरपालिकाओं के डंपिंग स्टेशनों पर दबाव कम पड़ेगा। नागरिकों में जागरूकता और व्यावहारिक अनुपालन की कमी के साथ ही नगरपालिकाओं के पास भी वित्त और तकनीकी संसाधनों की कमी है जिससे इस समस्या के समाधान में कई समस्याएं आ रही हैं। आज भारत के तमाम शहरों, गांवों, मोहल्लों में कचरे के ढेर देखने मिलते हैं, जबकि वहां प्रतिदिन कचरा संग्रहण के लिए गाड़ियां आती हैं। शहरों में इधर-उधर फैल रहा सिंगल-यूज प्लास्टिक और अन्य कचरा मानव सभ्यता पर कलंक के समान है। उदाहरण के लिए मुंबई शहर में प्रतिदिन 10,000 मेट्रिक टन कचरा पैदा होता है। यह शहर ई-कचरा में भी अग्रणी है। ऐसे में नगर-निकाय कितना भी प्रयास कर लें, नागरिक भागीदारी के बिना कचरा प्रबंधन नहीं हो सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अकादमिक प्रकाशनों में से एक 'नेचर जर्नल' के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है जहां से प्रतिवर्ष 93 करोड़ टन प्लास्टिक अपशिष्ट, जो विश्व का लगभग 20 प्रतिशत है, उत्पादित होता है। इसमें अधिकांश भाग सिंगल-यूज प्लास्टिक का है। 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (सीपीसीबी) के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 165 मेट्रिक टन हो जाएगा। 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (सीएसई) द्वारा साल 2020 में किए गए शोध के अनुसार भारत में 3159 कचरे के पहाड़ हैं जिनमें 80 करोड़ टन कचरा मौजूद है। 'संयुक्त राष्ट्र संघ' द्वारा तय किए गए 17 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' (एसडीजी) में सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छ भूमि के दो प्रमुख लक्ष्य भी हैं जिनमें ठोस कचरा प्रबंधन भी शामिल है।

हाल की प्रदूषित पानी की दुर्घटना और नतीजे में करीब दस लोगों की मौतें और सैकडों की बीमारी ने इंदौर की साफ-सफाई पर धब्बा लगा दिया है। एक तरफ, 'स्वच्छता सर्वेक्षणों' में वर्ष 2016 से इंदौर लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। यहां कचरा पृथक्करण, 'डोर टू डोर कलेक्शन,' आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट, बायोएनर्जी और कंपोस्टिंग, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन इत्यादि बहुत सी तकनीकें हैं जिनसे जनभागीदारी पर आधारित 'इंदौर मॉडल' सामने आया है। इसमें कचरे से ऊर्जा और खाद भी बनाई जा रही है। 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडल पर 'ग्रीन वेस्ट प्लांट' लगाया गया है और उन्नत लैंडफिल और 'बायो-रेमेडिएशन' किया गया है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद शहर में प्रदूषित पानी का संकट गंभीर बना हुआ है। जाहिर है, इंदौर का साफ-सफाई में अव्वल रहना उतना चमकदार नहीं है, जितना सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है। कहा जाता है कि इंदौर में स्वच्छता की वजह जनभागीदारी और जागरूकता है। इंदौर के निवासियों ने स्वच्छता को एक आदत बनाया है और इस कारण इंदौर में स्वच्छता एक सांस्कृतिक मानदंड बन गई है, लेकिन हाल की दुखद दुर्घटना ने स्वच्छ इंदौर बनाने में लगे प्रशासन, समाज और राजनेताओं पर कई सवाल खडे कर दिए हैं।

(लेखक 'सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी' के 2013 से सदस्य एवं 'पाठक मंच' के सचिव हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

ईरान में नए साल पर हिंसक हुए प्रदर्शन, महंगाई और सत्ता के खिलाफ बढ़ता आक्रोश

(एजेन्सी)।

नए साल की शुरूआत के साथ ही ईरान में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। बीते करीब एक हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में अब तक कम से कम सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। यह जानकारी ईरानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के हवाले से सामने आई।

बता दें कि नए साल के आगमन के साथ यह विरोध सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण इलाकों तक फैल गया है। राजधानी तेहरान से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी प्रांतों तक सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें देखी गई हैं। इससे पहले तेहरान की यूनिवर्सिटियों के छात्र सड़कों पर उतरे थे और तानाशाह को मौत जैसे नारे लगाए गए थे। कई जगहों पर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे सुनाई दिए।

गौरतलब है कि अमेरिका में निर्वासन में रह रहे शाह के बेटे रजा पहलवी ने सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों के समर्थन में संदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा कि वह ईरान के लोगों के साथ हैं और उनका दावा है कि मौजूदा शासन के रहते देश की आर्थिक स्थिति और खराब होती जाएगी। यह विरोध प्रदर्शन पिछले तीन वर्षों में सबसे बड़े माने जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह तेजी से बढ़ती महंगाई और मुद्रा की गिरती कीमत बताई जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, पश्चिमी ईरान के लोर्देगन, कुहदश्त और इस्फहान जैसे इलाकों में मौतों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े मीडिया संस्थानों ने लोर्देगन में झड़पों के दौरान दो लोगों की मौत की बात कही है, जबकि मानवाधिकार समूहों का दावा है कि यहां सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कई लोग मारे गए और घायल हुए।

कुहदश्त में बसीज स्वयंसेवी बल के एक सदस्य की मौत की पुष्टि की गई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने हालात का फायदा उठाया, जबकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मृतक प्रदर्शन में शामिल था और उसे सुरक्षा बलों ने गोली मारी है। इस्फहान प्रांत में भी एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है, हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

प्रदर्शन मार्वदश्त, करमानशाह, खुजेस्तान और हमदान जैसे इलाकों में भी फैले हैं, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाजार बंद हैं और व्यापारी, छात्र और आम लोग सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर हैं। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने एक ओर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं, तो दूसरी ओर संवाद की बात भी कही है। सरकारी प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने कहा है कि व्यापारी संगठनों और यूनियनों से बातचीत की जाएगी।

गौरतलब है कि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव में है। दिसंबर में महंगाई दर 42 प्रतिशत से अधिक बताई गई है और 2025 के दौरान ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले करीब आधी रह गई है। जून में इजरायल और अमेरिका के हवाई हमलों के बाद हालात और बिगड़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही आर्थिक दबाव मौजूदा जनआक्रोश की सबसे बड़ी वजह बन रहा है और आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

तंबाकू पर बढ़ा सरकारी टैक्स

(एजेन्सी)।

शेयर बाजार में बुधवार को आईटीसी लिमिटेड के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई, जो पिछले लगभग छह वर्षों में सबसे बड़ी रही। इसका कारण सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों पर लगाए गए उच्च कर को बताया जा रहा है। मौजूद जानकारी के अनुसार, फरवरी 1 से सिगरेट पर प्रति 1,000 स्टिक 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक का उत्पाद शुल्क लागू होगा।

बता दें कि इस बढ़े हुए शुल्क के साथ ही राष्ट्रीय आपदा कर भी जारी रहेगा, जिससे विश्लेषकों का अनुमान है कि कुल टैक्स में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। आईटीसी के शेयर में 10% तक गिरावट आई, जबकि गोदफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मुंबई में 17% नीचे बंद हुए। दोनों कंपनियों के ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य के मुकाबले 20 गुना अधिक रहे। आईटीसी क्लासिक और गोल्ड फ्लेक जैसी सिगरेट ब्रांड बेचती है, जबकि गोदफ्रे मार्लबोरो और फोर स्क्वायर जैसे ब्रांड का संचालन करती है।

गौरतलब है कि आईटीसी की कुल आय का 40% हिस्सा सिगरेट से आता है, इसलिए इस कर वृद्धि से कंपनी की बिक्री पर असर पड़ने की संभावना है। जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप के विश्लेषकों का कहना है कि अगर कीमतों में वृद्धि ग्राहकों पर डाली जाती है, तो कम से कम 15% तक बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।

मौजूदा कर वृद्धि, वस्तु एवं सेवा कर 40% के साथ लागू होगी और इसका मकसद सितंबर में किए गए व्यापक टैक्स कटौती से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह कदम तंबाकू उत्पादों की कीमत को उच्च बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की दिशा में एक प्रभावी उपाय है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे तंबाकू उत्पादों की तस्करी या ग्रे मार्केट के बढ़ने का जोखिम नहीं है।

भारत में 2.53 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा कर भी लागू किया है, और मार्च में IPL में इन उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। आईटीसी और गोदफ्रे फिलिप्स की ओर से अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कर वृद्धि से सिगरेट की कीमत में बढ़ोतरी होगी और इसका असर बाजार और उपभोक्ता दोनों पर दिखाई देगा।

चीन में गहराया जनसंख्या संकट, जन्म दर बढ़ाने के लिए कंडोम और गोलियों पर लगाया टैक्स

(एजेन्सी)।

चीन ने नए साल की शुरूआत से एक अहम फैसला लागू कर दिया है। अब देश में गर्भनिरोधक दवाओं और उपकरणों पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। करीब तीन दशक से जारी यह छूट 1 जनवरी से समाप्त हो गई है और अब कंडोम व गर्भनिरोधक गोलियों पर 13 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा रहा है, जो सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर लागू दर के बराबर है। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। लगातार तीसरे साल 2024 में भी चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट आने वाले वर्षों में भी जारी रह सकती है। इसी चिंता के बीच सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए अलग-अलग नीतिगत प्रयोग कर रही है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, चीन सरकार पहले ही बच्चों की परवरिश से जुड़े खर्चों को कम करने के लिए कई कदम उठा चुकी है। हाल ही में चाइल्डकेयर सब्सिडी को इनकम टैक्स से छूट दी गई थी और वार्षिक चाइल्डकेयर सहायता योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लव एजुकेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शादी, परिवार और बच्चों को लेकर सकारात्मक सोच विकसित की जा सके।

गौरतलब है कि हाल ही में हुई सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में चीन के शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा यह दोहराया कि विवाह और संतान को लेकर सकारात्मक माहौल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य गिरती जन्म दर को स्थिर करना बताया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में जनसंख्या गिरावट के पीछे सिर्फ नीतियां ही नहीं, बल्कि तेज शहरीकरण, महंगी शिक्षा, बच्चों की परवरिश का खर्च, नौकरी की अनिश्चितता और धीमी होती अर्थव्यवस्था भी बड़ी वजह हैं। गौरतलब है कि चीन में 1980 से 2015 तक लागू एक-संतान नीति का असर आज भी जनसांख्यिकीय ढांचे पर साफ दिखाई देता है।

बॉर्डर 2 का पहला गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज

(एजेन्सी)। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म के बहुप्रतीक्षित गाने, घर कब आओगे का ऑडियो ट्रैक रिलीज कर दिया है। इस वर्शन को दर्शकों को ध्यान में रखते हुए, मॉडर्न टच के साथ रिक्रिएट किया गया है। सोनू निगम ने कई पॉपुलर म्यूज़िशियन के साथ मिलकर घर कब आओगे गाना गाया है। इसका वीडियो आज, 2 जनवरी को शाम 6 बजे रिलीज किया जाएगा। जहां फैंस बॉर्डर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं वे संदेशे आते हैं के रिक्रिएटेड वर्शन, जिसका टाइटल घर कब आओगे है, का भी इंतजार कर रहे थे। जैसा कि वादा किया गया था, मेकर्स ने अब ऑडियो ट्रैक रिलीज कर दिया है। घर कब आओगे गाने के लिए जिन म्यूज़िशियन को क्रेडिट दिया गया है, वे हैं अनु मलिक, मिथुन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ, जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर।

सिडनी टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कह देंगे अलविदा-उस्मान ख़्वाजा

(एजेन्सी)।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख़्वाजा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वह सिडनी में खेले जाने वाले मौजूदा एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। बता दें कि 39 वर्षीय उस्मान ख़्वाजा इस टेस्ट में अपना 87वां मुकाबला खेलेंगे और अपने करियर का अंत 6206 रन और 16 शतकों के साथ करेंगे। उन्होंने यह घोषणा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपने परिवार की मौजूदगी में की, जहां उनका अंतरराष्ट्रीय सफर शुरू भी हुआ था और अब समाप्त भी होने जा रहा है।

मौजूद जानकारी के अनुसार ख़्वाजा ने कहा कि वह काफी समय से इस फैसले पर विचार कर रहे थे और एशेज सीरीज शुरू होने से पहले ही उन्हें आभास हो गया था कि यह उनका आखिरी दौरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस फैसले को लेकर उन्होंने अपनी पत्नी रेचल से भी कई बार बातचीत की थी और चयनकताओं को भी इसकी जानकारी दी थी।

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड चाहते थे कि ख़्वाजा आगे भी खेलते रहें और उन्हें भारत दौरे तक टीम में बनाए रखने की योजना थी, लेकिन ख़्वाजा ने सम्मानजनक विदाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने साफ कहा कि वह सिर्फ खेलने के लिए टीम में नहीं टिकना चाहते थे और अगर टीम को उनकी जरूरत नहीं होती तो वह तुरंत हटने को तैयार थे। इस सीरीज के दौरान पीठ की चोट के कारण वह एक टेस्ट से बाहर भी रहे थे और एडिलेड टेस्ट में शुरूआत में उन्हें टीम में नहीं चुना गया था। हालांकि स्टीव स्मिथ के बीमार होने के बाद उन्हें मौका मिला, जहां उन्होंने अहम 82 रन बनाकर यह साबित किया कि वह अब भी टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज हैं।

बता दें कि ख़्वाजा ने 2010-11 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी बने थे। शुरूआती संघर्षों, टीम से बाहर होने और वापसी की कहानी ने उनके करियर को खास बनाया। 2021-22 की एशेज सीरीज में दो शतक लगाकर उन्होंने खुद को फिर से स्थापित किया और उसके बाद लंबे समय तक टीम की रीढ़ बने रहे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि उस्मान ख़्वाजा ने मैदान के भीतर और बाहर दोनों जगह असाधारण योगदान दिया है और उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। ख़्वाजा ने यह भी कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलते रहेंगे और घरेलू क्रिकेट में क्वींसलैंड के लिए भी उपलब्ध रह सकते हैं।

गौरतलब है कि उनके संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग स्लॉट के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे, खासकर अगस्त में होने वाली बांग्लादेश सीरीज से पहले। फिलहाल जैक वेदराल्ड और ट्रैविस हेड विकल्प बने हुए हैं, लेकिन उनकी जगह पक्की नहीं मानी जा रही है।

गरिमापूर्ण, अनुशासित एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह: डीसी अपराजिता

राष्ट्र भक्ति पर आधारित हो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। डीसी अपराजिता ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पुलिस लाइन मैदान में गरिमापूर्ण, अनुशासित एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से मनाया जाएगा। इसमें देश भक्ति व विभिन्न लोक संस्कृति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल से कार्य करें और अपने विभाग से संबंधित तैयारियां करना शुरू करें।

डीसी अपराजिता लघु सचिवालय स्थित सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह के भव्य आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी।

डीसी ने ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाओं पर गहनता से समीक्षा की और अधिकारियों को ड्यूटियां सौंपी। डीसी ने कहा कि समारोह में जो भी झांकियां शामिल हों, वे विशेष थीम पर आधारित होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस समारोह में प्लाटून द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया जाएगा। परेड में शामिल टुकड़ियों द्वारा 18 से 23 जनवरी को पुलिस लाइन मैदान में पूर्वाभ्यास किया जाएगा तथा 24 जनवरी को फुल ड्रैस फाइन रिहर्सल निर्धारित समयानुसार किया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए कि सभी प्लाटून की परेड से संबंधित तैयारियां अपने मार्गदर्शन में तैयार करवाएं।

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के निर्धारित समयानुसार सुबह 10 बजे मुख्यातिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इससे पहले मुख्यातिथि द्वारा शहर में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे।

मुख्यातिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया जाएगा तथा जिला वासियों को संबोधित करेंगे व भव्य मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस दौरान पीटी शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय गान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस विभाग, डीआरडीए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, सहकारी चीनी मिल, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, आईसीडीएस, रोजगार विभाग, जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र, आयुष विभाग, खेल विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, रैडक्रास सोसायटी सहित अन्य विभागों द्वारा झांकियां निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन झांकियों को भव्य रूप देते हुए विभाग की योजनाएं व उपलब्धियों को प्रदर्शित करें, ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल सके।

डीसी अपराजिता ने कहा कि समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। जिनका चयन जिला परिषद के सीईओ की अध्यक्षता बनाई गई चार सदस्यों की कमेटी करेगी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। सभी विभागाध्यक्ष 20 जनवरी से पहले अपने विभाग से संबंधित नामों को अनुमोदन भिजवाना सुनिश्चित करें। एडीसी की अध्यक्षता में बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी नामों को फाइनल करेगी।

इस अवसर पर एसपी उपासना, एडीसी सुशील कुमार, डीएमसी कपिल शर्मा, जिला परिषद के सीईओ सुरेश रावि‍श, एमडी शुगर मिल कृष्ण कुमार, आरटीए गिरिश कुमार, एसडीएम कलायत अजय हुड्डा, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीआईओ दीपक खुराना, डीआरओ चंद्रमोहन, डीडीपीओ रितू लाठर, डीआईपीआरओ नसीब सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दहा जागीर में 1.66 करोड़ के सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने आज नगर निगम के वार्ड छह में स्थित गांव दहा जागीर में एक करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नव वर्ष पर नशे से दूर रहने का संकल्प लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम की ओर से सामुदायिक केंद्र का निर्माण आठ माह में पूरा किया जाएगा। केंद्र में बेसमेंट सहित भूतल बनाया जाएगा, जहां दोनों तल पर करीब दो-दो सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। सामुदायिक केंद्र का कुल कवर्ड क्षेत्र 5122 वर्ग फुट रहेगा। उन्होंने लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की केवल सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है।

श्री कल्याण ने कहा कि युवाओं का नशे की ओर बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संविधान निमार्ता बाबा साहेब अंबेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और संकल्प से ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी और रिंग रोड के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही उन्होंने पिछले दस वर्षों में हलके में कराए गए प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी भी दी। सामुदायिक केंद्र बनने के बाद ग्रामीणों को सामाजिक कार्यक्रमों व सुख-दुख में इसका लाभ मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को शामलात भूमि की चारदीवारी, खेल मैदान की योजना तैयार करने तथा सड़कों को इंटरलॉकिंग से बनाने के निर्देश दिए। पेंशन कटने की शिकायतों पर उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं कटने दी जाएगी।

इससे पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तुरंत उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने बताया कि सामुदायिक केंद्र से संबंधित पूरा विवरण एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा गांव के सरकारी भवनों की देखभाल पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर वार्ड पार्षद अंकित तितोरिया, नगर निगम की कार्यकारी अभियंता प्रियंका सैनी, एसडीओ प्रेम सैनी, भाजपा नेत्री मंजू खैंची, निशांत राणा, महावीर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आमजन की शिकायतों का समयबद्ध किया जाए निपटान: डीसी अपराजिता

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों की समीक्षा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। डीसी अपराजिता ने कहा कि सोमवार और वीरवार को समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को अधिकारी पूर्णतः गंभीरता से लें। शिविर के दौरान जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें पोर्टल करें और उनका समाधान समयबद्ध किया जाए। यदि कोई अधिकारी इन शिकायतों के निपटान में लापरवाही बरतेगा तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

डीसी अपराजिता शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। डीसी अपराजिता ने बताया कि जिन विभागों की शिकायतें लंबित पड़ी हुई है, उनका जल्द समाधान करते हुए आमजन को राहत प्रदान करें। समाधान शिविर सरकार के सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारने का एक प्रभावी माध्यम है। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए। गुणवत्तापूर्ण एटीआर पोर्टल पर अपलोड की जाए ताकि वह शिकायत दोबारा से न खुले। जिन शिकायतों का समाधान संभव नहीं है, उन्हें रिजेक्ट की श्रेणी में डाले।

इस अवसर पर एसपी उपासना, एडीसी सुशील कुमार, डीएमसी कपिल शर्मा, जिला परिषद के सीईओ सुरेश रावि‍श, एमडी शुगर मिल कृष्ण कुमार, आरटीए गिरिश कुमार, एसडीएम कलायत अजय हुड्डा, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीआईओ दीपक खुराना, डीआरओ चंद्रमोहन, डीडीपीओ रितू लाठर, डीआईपीआरओ नसीब सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

विदेशी नागरिकों की सूचना समय पर देना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा है कि भारत सरकार के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत विदेशी नागरिकों (ओसीआई कार्डधारकों सहित) के ठहरने, अध्ययन व इलाज से संबंधित जानकारी तय समय सीमा में देना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि सभी होटल संचालक, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान तथा आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाले अन्य निकायों को किसी भी विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर फॉर्म-3 (पूर्व में फॉर्म-सी) ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप इंडियन वीजा सुस्वागतम के माध्यम से पंजीकरण अधिकारी को भेजना होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत होटल, गेस्ट हाउस, होम-स्टे, पीजी, सराय, टेंट, किराये के मकान, अस्पताल व नर्सिंग होम (विदेशी मरीज व उनके सहायक), विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल (हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्र), धार्मिक संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट और सार्वजनिक संगठनों को विदेशी नागरिक के आगमन, प्रस्थान तथा अगले गंतव्य से संबंधित विवरण कम से कम एक वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह रिकॉर्ड किसी भी समय पंजीकरण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी (हेड कांस्टेबल रैंक से ऊपर) द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जा सकता है। नियमों की अवहेलना करने पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राजौंद में पीएमएवाई आवास योजना की किस्तें जारी, 1 करोड़ 16 लाख रुपए लाभार्थियों के खातों में पहुंचे

चेयरपर्सन बबीता बोलीं-मुख्यमंत्री हरियाणा व प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से नगर में नहीं है विकास कार्यों की कोई कमी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। राजौंद में 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी सौगात दी गई है। योजना के तहत 48 लाभार्थियों को दूसरी किस्त तथा 144 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई है। इस प्रक्रिया में कुल 1 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि पात्र लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। नपा चेयरपर्सन बबीता ने यह जानकारी प्रैस कान्फ्रेंस में दी है।

नगर पालिका चेयरपर्सन बबीता ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से राजौंद में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजौंद क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और वर्ष 2026 में राजौंद में और भी तेज गति से विकास कार्य होंगे।

चेयरपर्सन ने बताया कि नगर के जींद मार्ग पर वार्ड नंबर 7 व 8 के पास अंबेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत पीएमएवाई-2 की 75 से 80 फाइलें तैयार हो चुकी हैं, जिनके पात्र लाभार्थियों के खातों में सभी औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र ही भुगतान ट्रांसफर किया जाएगा।

नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि राजौंद की टूटी सड़कों का मुद्दा उपायुक्त कैथल की बैठक में उठाया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कार्यालय के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास वार्ड नंबर 4 के पार्क परिसर, शौपिंग काम्प्लेक्स के पास, पेगा मार्ग पर समुदायिक भवन के पास आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों की मांग पर सरकारी अस्पताल के बाहर ओपन शौचालय का निर्माण भी करवाया जाएगा।

सचिव ने आगे बताया कि कैथल मार्ग पर रेन बसेरा के पास एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसकी चारदीवारी भी तैयार की जाएगी। इससे नगर के युवाओं को एक बेहतरीन अध्ययन केंद्र उपलब्ध होगा। इसके अलावा कैथल मार्ग पर रेन बसेरा बनाया गया है, जिसमें 16 बेड की व्यवस्था की गई है, ताकि रात में रुकने वाले राहगीरों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि नगर की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को किराए पर देने के लिए फाइल डीसी कार्यालय भेजी गई है, मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वार्ड नंबर 4 की गली 26 जनवरी तक तैयार होने की सम्भावना है।

एक सवाल के जवाब में नपा सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी गली में अवैध चबूतरे या रैंप बने होने की शिकायत मिलती है तो उन्हें हटाया जाएगा। सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता शिकायत मिलने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि डोर-टू-डोर कूड़ा वाहन में ही कचरा डालें और पॉलिथीन या कचरा नालियों में न फेंकें, जिससे नालियां जाम हो जाती हैं।

इसके अलावा गुरु ब्रह्मानंद आश्रम वाली गली का टेंडर हो चुका है और जल्द ही गली का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया जाएगा।

इस अवसर पर चेयरपर्सन बबीता, नपा सचिव नरेंद्र शर्मा, जेई अश्विनी कुमार, प्रदीप कुमार (कोऑर्डिनेटर), मार्केट यूनियन प्रधान भीम सिंह राणा, सचिन प्रजापति, सफाई निरीक्षक प्रदीप कुमार, महेंद्र शर्मा, राहुल, पार्षद कर्मपाल, भाजपा नेता कपिल दीक्षित, पार्षद जॉनी राणा, मनीराम, विजेंद्र राणा उर्फ बोगल राणा, पार्षद प्रतिनिधि सोनू राणा, शेखर शर्मा, विशाल कुमार सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

असंध में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न

रोशन लाल शर्मा को चेयरमैन व हिसम सिंह को प्रधान चुना

संजना भारती संवाददाता

असंध। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन सम्बंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शाखा असंध का त्रिवार्षिक चुनाव उप मण्डल कार्यालय के प्रांगण में सम्पन्न हुआ।

चुनाव प्रक्रिया चुनाव पर्यवेक्षक राज्य महासचिव सन्दल सिंह राणा व प्रचार सचिव ओमदत्त शर्मा की अगुवाई में हुआ। चुनाव में सर्वसम्मति से ब्रांच की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें रोशन लाल शर्मा को चेयरमैन, हिसम सिंह उपलाना को प्रधान तथा धर्मपाल सिन्हा को सचिव चुना गया। इसके अतिरिक्त कर्मबीर को वरिष्ठ उपप्रधान, सोनू शर्मा को उपप्रधान, कुलदीप शर्मा को कोषाध्यक्ष, धीरज शर्मा को सह कोषाध्यक्ष, विक्रम शर्मा को सह सचिव, विकास जूड को प्रेस सचिव, दीपक कुमार को मुख्य सलाहकार, हरीश भार्गव को संगठन सचिव तथा मीनू शर्मा को ऑडिटर चुना गया।

नवनियुक्त पदाधिकारियों का फुल मालाए पहनाकर स्वागत किया गया।

50 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा का महा उत्सव

संजना भारती संवाददाता

शाहदरा, शिवाजी पार्क स्थित लिटिल फ्लावर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दो दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम युगांतर को विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को समर्पित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा (केंद्रीय राज्य मंत्री), डॉ. प्रज्ञा एम. सिंह (प्रो. एवं डायरेक्टर एकेडमिक, सीबीएसई), डॉ. महेश वर्मा (कुलपति, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय) सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय की प्रबंधिका सी.एम. पटेल, प्रधानाचार्या नीता दुआ तथा लिटिल फ्लावर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंध निदेशक आर.डी. पटेल द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया।

उल्लेखनीय है कि लिटिल फ्लावर्स विद्यालय की स्थापना 10 मई 1975 को महान शिक्षाशास्त्री, समाजसेवी एवं संस्थापक प्राचार्य स्वर्गीय धनराज पटेल तथा उनकी सहधर्मिणी सी.एम. पटेल द्वारा की गई थी। बीते पाँच दशकों में यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों के क्षेत्र में एक सशक्त पहचान बनाकर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है।

स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत भव्य नृत्यनाटिका में भारतीय सभ्यता के चारों युग-सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की अद्भुत झलक देखने को मिली। राम, कृष्ण, वराह एवं नरसिंह अवतार की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने भारतीय जीवन मूल्यों, धर्म और कर्तव्यबोध को जीवंत कर दिया, जिसे दर्शकों ने मुक्त कंठ से सराहा।इसी कड़ी में प्रस्तुत कार्यक्रम द एसेंस ऑफ लाइफ ने सभी को भावविभोर कर दिया। एक रहस्यमय वेश-भूषा एवं सशक्त मंच प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों ने निर्मल यमुना और गंगा अवतरण की पावन कथा को नृत्यनाटिका के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने पर्यावरण संरक्षण और जीवनदायिनी नदियों के महत्व का सशक्त संदेश दिया।

इस स्वर्णिम अवसर को और भी विशेष बनाते हुए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली डाक परिमंडल, नई दिल्ली द्वारा विद्यालय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विशेष डाक आवरण जारी किया गया, जो विद्यालय के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बना।

मुख्य अतिथियों ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों में कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक चेतना और मूल्यों की सराहना की तथा प्रबंधन समिति को स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रदान कीं।

मैत्री मैच में शेरपुर टीम ने मऊ टीम को 9 विकेट से हराया

एसबी संवाददाता

विद्यापतिनगर। प्रखंड अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मऊ बाजिदपुर उत्तर (मिर्जापुर) के क्रीड़ा मैदान में नव वर्ष के उपलक्ष्य में दूसरे दिन शुक्रवार को आरजे कप एकदिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता कुणाल कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त व बल्लेबाजी कर मैच का आगाज किया। उन्होंने कहा कि खेल से न केवल मानसिक, शारीरिक विकास होता हैं बल्कि खेल से सामाजिक समरसता और सामूहिकता को भी बढ़ावा मिलता हैं। मऊ टीम व शेरपुर टीम के बीच खेले गए मैच में मऊ टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10.4 ओवरों में महज 54 रन पर ही सिमट गई। शेरपुर की ओर से निखिल ने 21 रन खर्च कर 4 विकेट झटके।

वहीं नवीन व राहुल ने 2-2 विकेट प्राप्त किए। मऊ टीम की ओर से शांतनु ने 14 रनों का योगदान दिया। सर्वाधिक 19 रन अतिरिक्त की मदद से बने। जवाबी पारी में शेरपुर टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज शिवम हर्ष ने 3 गगनचुंबी छक्कों व 2 चौके की मदद से शानदार 33 रन बनाएं। वहीं शिबू ने 15 रनों का योगदान दिया। शेरपुर की टीम ने 4.1 ओवरों में 1 विकेट खो कर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच शेरपुर टीम के निखिल स्टार्क व सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज शिवम हर्ष को घोषित किया गया।

मुख्य अतिथि यूथ ब्रिगेड के संयोजक पदमाकर सिंह लाला ने विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि पदमाकर सिंह लाला ने खेल की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि खेल के जरिए हम सामाजिक कुरीतियों मसलन जाति, धर्म, वर्ग विभेद, उच्च-नीच और गरीबी-अमीरी का अतिक्रमण करते हुए टीम भावना के साथ आत्मीय रूप से संगठित होते हैं। खेल शारीरिक, मानसिक और सामाजिक का आयाम हैं। आयोजक समाजसेवी ऋतुराज चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। निर्णायक की भूमिका चंदन कुमार भोला व विशाल कुमार ने निभाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. बृजेश कुमार सिंह बदायूं को किया गया सम्मानित

संजना भारती संवाददाता

बदायूं। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली महोदय रमित शर्मा द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली अजय कुमार साहनी के साथ जोन कार्यालय बरेली में आयोजित Pipping Ceremony में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूँ, डॉ. बृजेश कुमार सिंह को सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त होने पर रैंक प्रतीक चिन्ह एवं कॉलर बैंड लगाकर प्रोन्नति की बधाई देते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवारा कुत्तों की ग्राम पंचायतों में नसबंदी व टीकाकरण होगा: डीडीपीओ

एसबी संवाददाता/कैथल। डीडीपीओ रितु लाठर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवारा कुत्तों को जिला की सभी ग्राम पंचायतों में नसबंदी और टीकाकरण का कार्य किया जाना है। जिसके लिए खंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कैथल खंड के लिए एसईपीओ अनुराग दत्त (9466878771), ढांड खंड के लिए सहायक चांदी राम (9896100530), गुहला के लिए एसईपीओ चंचल (7988054279), राजौंद के लिए सहायक बदन सिंह (9467084057), कलायत के लिए सहायक बलवान सिंह (9017096200), पूंडरी के लिए एसईपीओ प्रवीन कुमार (9991973973) तथा सीवन के लिए अनुज (9671960254) को नोडल अधिकारी लगाया गया है।

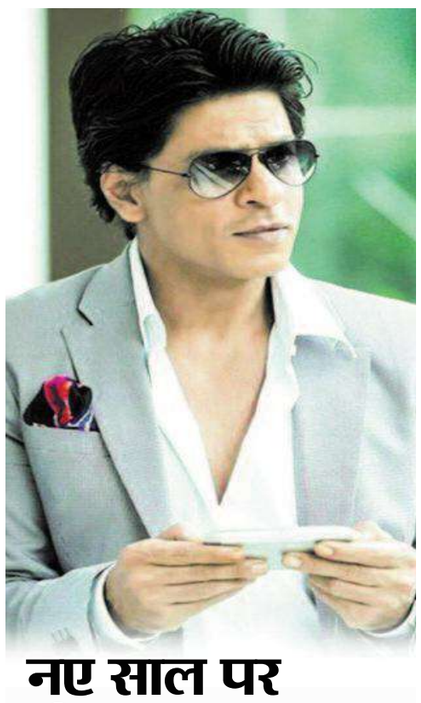

नए साल पर 'किंग' को लेकर शाहरुख खान देंगे बड़ा तोहफा!

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म 'किंग' की तैयारियों में लगे हुए हैं। 'किंग' को साल 2026 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है। इस बीच अब शाहरुख खान को रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते देखा गया। जिसके बाद फैंस में 'किंग' को लेकर एक बार फिर उत्साह बढ़ गया है। फैंस ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि नए साल पर 'किंग' को लेकर कोई सरप्राइज मिल सकता है। 'किंग' पर काम कर रहे शाहरुख वायरल हुई तस्वीरों और वीडियोज में शाहरुख को फिटेड सफेद टी-शर्ट और कार्गो पैंट पहने, सिर पर बीनी टोपी लगाए देखा गया। स्टूडियो में अंदर जाते समय उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे। हालांकि, अभिनेता क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उनके स्टूडियो में आने के समय को देखते हुए प्रशंसकों का मानना है कि वो अपनी आगामी फिल्म 'किंग' के पोस्ट-प्रोडक्शन क्लिप पर काम कर रहे होंगे। हालांकि, इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने शाहरुख को पैपराजी से बचान का प्रयास किया और उनके सामने छाता लगाया। लेकिन शाहरुख की झलक कैमरे में कैद हो गई। अब फैंस को उम्मीद है कि नए साल पर उन्हें शाहरुख की तरफ से 'किंग' से जुड़ा कोई सरप्राइज मिल सकता है।

शाहरुख के बर्थडे पर सामने आया था फर्स्ट लुक

पिछले महीने शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने 'किंग' से शाहरुख के लुक की झलक दिखाई थी। इस फर्स्ट लुक में शाहरुख एक्शन अवतार में काफी डैशिंग लग रहे थे। इसके सामने आने के बाद फैंस फिल्म को लेकर और भी उत्साहित हैं। हालांकि, इसके बाद से किंग को लेकर मेकर्स की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। अब फैंस ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि अगली बड़ी घोषणा नए साल के दिन हो सकती है।

सिद्धार्थ ने भी दिया था हिंट

शाहरुख खान को स्टूडियो में देखे जाने से एक दिन पहले फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने एक शेर के मोहरे की तस्वीर साझा की थी, जिसके सिर पर मुकुट था। अब शाहरुख को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखकर फैंस ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि मेकर्स मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट घोषित कर सकते हैं।

अब मैं एक साथ 2 से 3 फिल्में नहीं करना चाहती

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल 2022 को मुंबई में अपने घर वास्तु में एक अंतरंग समारोह में शादी की थी। इसके बाद 6 नवंबर 2022 को आलिया ने राहा को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद से ही आलिया भट्ट ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ बदलाव किए हैं, जिनके बारे में आलिया ने खुलकर बात की।

राहा के जन्म के बाद आलिया ने किए कई बदलाव

हाल ही में ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने बताया कि 2022 में बेटी राहा के जन्म के बाद उन्होंने काम की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन फिल्मों से उनका प्यार वैसा ही है। आलिया ने कहा कि मां बनने से उनके काम करने का तरीका बदल गया है। उन्होंने बताया, अब मेरे काम की मात्रा और स्पीड अलग है क्योंकि मेरी एक बेटी है। लेकिन यह रफ्तार आरामदायक है और मैं इससे खुश हूं। मुझे एक समय में एक फिल्म करना और उसमें पूरी एनर्जी लगाना अच्छा लगता है। पहले मैं एक साथ दो-तीन फिल्में करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहती।

अल्फा को लेकर आलिया की राय

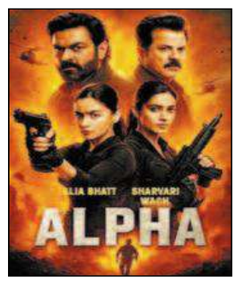

मां बनने के बाद एक्शन फिल्म अल्फा की शूटिंग के बारे में आलिया ने कहा, बच्चे के जन्म के बाद एक्शन करना बहुत मजेदार था। इससे मुझे पता चला कि मेरा शरीर क्या कर सकता है। यह एक सीख देने वाला अनुभव था और इसने मुझे अपने शरीर का बहुत सम्मान करना सिखाया।

आलिया का वर्कफंट

आलिया के पास दो बड़ी फिल्में हैं। शिव रावैल की अल्फा में वे एक्शन से भरी भूमिका में नजर आएंगी। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसमें शरवरी और बॉबी देओल भी हैं। फिल्म 2026 में रिलीज होगी। इसके अलावा, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में आलिया दिखेंगी। इसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म भी 2026 में आएगी।

हिंदी में इस वजह से बात नहीं करते मिराय स्टार तेजा सज्जा

फिल्म हनु मान और मिराय में बेहतरीन अदाकारी करने को लेकर साउथ के स्टार तेजा सज्जा सुर्खियों में हैं। यह माना जाता है कि साउथ के कलाकारों को हिंदी डायलॉग बोलते समय उनके एक्सेंट को लेकर ऑनलाइन मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे में तेजा सज्जा ने हिंदी बोलने पर और बॉलीवुड में काम करने को लेकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी हिंदी में हैदराबादी स्लैंग आ जाता है। अगर हिंदी बोलेंगे तो ट्रोलिंग का शिकार हो जाएंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा नहीं मैं ट्रोलिंग को सीरियसली नहीं लेता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातचीत के दौरान उन्होंने बॉलीवुड में काम करने के बारे में भी बात की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में फिल्म निर्माता करण जौहर के लिए एक संदेश दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा जब भी आप करण सर से मिलें, उनसे पूछिएगा कि वह तेजा को एक धर्मा प्रोडक्शन की लव स्टोरी में कब कास्ट कर रहे हैं। मैं भी वो अनुभव लेना चाहूंगा।

मैं नहीं चाहती कि हॉलीवुड प्रोजेक्ट की वजह से करियर खतरे में पड़ जाए

अभिनेत्री त्रिधा चौधरी हाल ही में फिल्म 'किस किस को प्यार करूं-2' में नजर आई थीं। अभिनेत्री ने हाल ही में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर के बारे में खुलकर बात की। अभिनेत्री ने बताया कि वह अलग-अलग फिल्म को बहुत सोच समझकर चुनती हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हॉलीवुड से एक अच्छा ऑफर मिला था, लेकिन बोल्ड सीन्स करने से उन्हें बाकी जगह से ऑफर ठुकरा दिए जाते। अभिनेत्री ने कहा, 'मुझे अच्छी तरह से पता था कि ऐसे सीन करने से मेरा भविष्य प्रभावित हो सकता है। खासकर बॉलीवुड और अन्य भारतीय इंडस्ट्री में मौके कम हो जाते हैं। अभिनेत्री ने समझाया कि बोल्ड सीन करने से उन्हें एक खास तरह की इमेज मिल जाती है। इससे कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल सकते थे। वे नहीं चाहती थीं कि एक प्रोजेक्ट की वजह से उनका लंबे समय का करियर खतरे में पड़ जाए। उन्होंने कहा, 'अगर मैं हॉलीवुड में एक ऐसा प्रोजेक्ट करती, जिसमें बोल्ड सीन्स होते, तो इससे मेरे कई अन्य प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। मुझे यह पहले से पता था। यही वजह थी कि मैंने पहले से हॉलीवुड में कदम रख लिया है, तो अलग तरीके से आगे बढ़ सकती हूं, लेकिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड या कहीं और का अपना लंबा सफर जोखिम में नहीं डालूंगी।' त्रिधा हाल ही में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं-2 में नजर आई थी। फिल्म में कपिल और त्रिधा के अलावा, आयशा खान, पारुल गुलाटी और हीरा वरीना मुख्य भूमिका में नजर आए थे। अखिलेंद्र मिश्रा कपिल शर्मा के पिता के रोल में हैं। उन्होंने फिल्म के सबसे मजेदार पल दिए हैं। वहीं, फिल्म को वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास-मस्तान ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें हंसी, मस्ती, दोस्ती और खुशियों से भरे पल शामिल हैं।

तारा सुतारिया के खिलाफ चलाया गया नेगेटिव कैंपेन? अभिनेत्री ने लगाया जबरदस्ती नाम जोड़ने का आरोप

बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया में इन दिनों पेड पीआर और ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बहस के केंद्र में आ गई हैं अभिनेत्री तारा सुतारिया, जिन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ एक सोची-समझी नेगेटिव पीआर मुहिम चलाई जा रही है। तारा का कहना है कि उनकी छवि और निजी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित तरीके से कंटेंट तैयार करवाया गया और सोशल मीडिया पर फैलाया गया।

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने किया दावा

पूरा मामला तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने दावा किया कि उसे तारा सुतारिया और मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे। इस वीडियो को तारा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया और साफ शब्दों में कहा कि यह सब एक पेड कैंपेन का हिस्सा है, जिसका मकसद उनके करियर और पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाना है। तारा ने इशारों-इशारों में उन लोगों पर निशाना साधा, जो पर्दे के पीछे रहकर ऐसी साजिशें रचते हैं। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स और मीम पेजों को पहले से तय शब्द, कैप्शन और बातें भेजी गईं ताकि हर जगह एक जैसी नकारात्मक बातें फैलाई जा सकें। उनका यह भी कहना था कि यह कोई सामान्य आलोचना नहीं, बल्कि पूरी तरह प्लान की गई बदनाम करने की कोशिश है।

बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने किया समर्थन

इस पूरे विवाद में तारा को वीर का साथ मिला है। उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताते हुए कहा कि वह हर हाल में तारा के साथ खड़े हैं। वहीं, एपी ढिल्लों ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देकर यह संकेत दिया कि वह इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन मामला जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जिस इंफ्लुएंसर ने यह खुलासा किया, उसका कहना है कि कई अकाउंट्स पर एक जैसे कमेंट्स और आरोप नजर आ रहे थे। इससे साफ होता है कि यह सब अचानक नहीं, बल्कि रणनीति के तहत किया गया। इंफ्लुएंसर ने दावा किया कि इस मुहिम को बाहर से देखने पर ऐसा दिखाया गया जैसे निशाना एपी ढिल्लों हों, लेकिन असल में सबसे ज्यादा नुकसान तारा सुतारिया को पहुंचाने की कोशिश की गई।

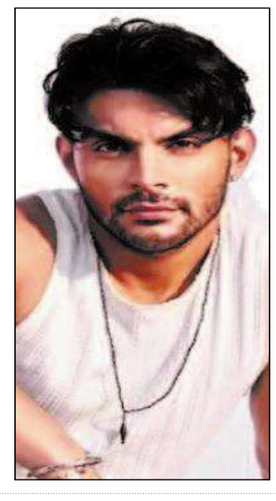

अकेली हूं पर कोई बेचैनी नहीं

चित्रांगदा सिंह ने साल 2005 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी से फिल्मों में डेब्यू किया। अपने करियर की शुरुआत से ही जोधपुर में पैदा हुई इस हसीना ने इंडस्ट्री में अपने अभिनय का सिक्का जमाया। अर्थपूर्ण भूमिकाओं को तरजीह दी। ये साली जिंदगी, इनकार, साहब बीवी गैंगस्टर 3 जैसी फिल्मों में उनके काम की खूब सराहना हुई। लेकिन उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर वो था, जब सात साल के अंतराल के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कमबैक किया। इस साल 2025 में वह बैक टू बैक खाकी - द बंगाल चैप्टर, हाउसफुल 5 और होलिया रिलीज रात अकेली है - द बंसल मर्डर्स से चर्चा में हैं। इसके अलावा चित्रांगदा नए साल में सलमान खान के साथ बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाली हैं।

बतौर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह 2026 को उम्मीदों से देख रही हैं। खास बातचीत में उन्होंने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सोशल मीडिया वैलिडेशन, सिंगल पैरेंटिंग से लेकर इंडस्ट्री में महिलाओं के ऊपर रहने वाले दबाव पर भी खुलकर बात की है।

आपका करियर कभी भी पारंपरिक नहीं रहा, तो क्या आपने जानबूझकर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चुना?

किसी भी कलाकार के जीवन में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसे किस तरह के रोल मिलेंगे, वो उसके बस में नहीं होता। कई बार काम आपको चुनता है, आप उसे नहीं। मुझसे सुधीर (फिल्मकार सुधीर मिश्रा) हमेशा कहते हैं कि किसी भी किरदार के जो ग्रे एरिया हैं, उन्हें तुम बखूबी जस्टिफाई कर पाती हो। यही वजह है कि तुम चरित्र की कमियों को बहुत ही मजबूती से निभा पाती हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेकर्स ने मुझमें वो बात देखी और मुझे उसी तरह के रोल दिए। कई बार मेरे पास ऐसा काम आया है, जो मुझे सूट नहीं हुआ और मैंने मना कर दिया, आपका अपना व्यक्तित्व भी होता है, जिसमें आप खुद को पूरी तरह से बदल कर कोई दूसरा नहीं बन सकते।

फिल्म इंडस्ट्री में उम्र को लेकर महिलाओं पर ज्यादा दबाव क्यों रहता है?

वो कहावत है न कि महिलाएं अपनी ब्यूटी और पुरुष अपने स्कार्स के लिए जाने जाते हैं। फिर ये उम्र वाली समस्या आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। मगर आज उसमें भी बदलाव आया है। आज आप एक यंग 18 साल की लड़की के रोल के लिए एक पर्टिकुलर ऐज ग्रुप वाली लड़की को ही चुन पाएंगे, मगर यदि आपको कोई मैच्योर कहानी लिखनी हो तो उसमें आपको मैच्योर एक्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। मगर अब वो बदलाव भी आ रहा है, क्योंकि अब दर्शक मैच्योर कहानियों और परफॉर्मेंस देखने के इच्छुक हैं, तो अब अभिनेत्रियों के लिए उम्र से परे सशक्त रोल लिखे जा रहे हैं, मगर उम्र का दबाव अभिनेत्रियों पर हमेशा से रहा है और ये हमारे समाज की ही देन है।

आपने पर्दे पर हमेशा ही महिलाओं को मुखर करने वाले किरदार निभाए हैं, आपको अपने आस-पास महिलाओं से जुड़ी सबसे ज्यादा कौन-सी बात सताती है?

सच कहूं, तो मुझे लगता है कि आज महिलाओं को समानता के अधिकार मिल रहे हैं। जेंडर बायस भी लोग अब उतने नजर नहीं आते, तो आज हमें इस बदलाव की सराहना करनी चाहिए। इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इंडस्ट्री में ये बदलाव काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, मगर हां कुछ एक बार मैंने ये देखा है कि लड़कियों को कोई काम इसलिए नहीं दिया जाता कि वो लड़कियां हैं। मुझे लगता है कि उसका एक कारण ये भी है कि औरतों को उस तरह की जिम्मेदारी दी ही नहीं गई है। उनको जितने मौके मिलेंगे, वो खुद को साबित करती जाएंगी। अब जैसे जब मैं प्रोड्यूसर बनी, तो लोगों का कहना था कि लो अब इनको प्रोड्यूसर बनना है। वे मुझे इस काबिल ही नहीं समझ रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, मगर मैंने जब इस विषय पर सोचा तो मुझे लगा कि वाकई इंडस्ट्री में एक?ट्रेस से प्रोड्यूसर बनी महिलाएं गिनती की हैं, तो उनका सवाल भी जायज है कि ये निर्माण के क्षेत्र को संभाल पाएंगी या नहीं।

सोशल मीडिया वैलिडेशन आपके लिए कितना मायने रखता है?

मैं सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा दीवानी नहीं हूं। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज सोशल मीडिया की जरूरत तो है। मेरे लिए सोशल मीडिया वैलिडेशन जरूरी नहीं है। मैं उसे रेस्पॉन्स तक ही सीमित रखती हूं। मैं सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखती हूं, मगर मेरी जिंदगी सोशल मीडिया पर ही निर्भर नहीं है। अब तो वो उत्साह भी खत्म हो गया है, जो पहले हुआ करता था कि कुछ पोस्ट करना है। अब ये मेरे काम का हिस्सा बन चुका है।